vinetur

डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस के सामने लॉबिंग में बीयर इंस्टीट्यूट का जोर एल्यूमिनियम, करों और हेम्प पर

ब्रायन क्रॉफर्ड ने कहा कि बीयर निर्माता संगठन कैन की लागत, उत्पाद शुल्क के बोझ और हेम्प-आधारित पेयों से जुड़ी नियामकीय अनिश्चितता पर सांसदों के सामने अपनी बात रखेगा

मंगलवार, 10 नवंबर 2026



Beer Business Daily की रिपोर्ट के अनुसार, समूह के अध्यक्ष ब्रायन क्रॉफर्ड ने कहा कि बीयर इंस्टीट्यूट नई, डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस के साथ काम शुरू करते हुए अपनी संघीय नीति-प्राथमिकताओं में एल्यूमिनियम, कर नीति और हेम्प को प्रमुखता देगा।

क्रॉफर्ड के संदेश से संकेत मिलता है कि चुनाव नतीजों के बाद कैपिटल हिल पर राजनीतिक संतुलन बदलने के चलते वॉशिंगटन में लॉबिंग और संपर्क अभियान फिर तेज होंगे। बीयर निर्माताओं के लिए उनके बताए मुद्दे व्यापार संगठनों की नियमित प्राथमिकताओं से आगे जाते हैं। इनका संबंध प्रमुख लागतों, उत्पाद प्रतिस्पर्धा और ऐसे नियमों से है जो व्यापक

पेय बाजार में भविष्य की वृद्धि को आकार दे सकते हैं।

Beer Business Daily ने बताया कि क्रॉफर्ड ने उस स्थिति के बाद नई कांग्रेस से संवाद की जरूरत बताई, जिसे प्रकाशन ने 'नीली लहर' कहा। बड़े और छोटे बीयर निर्माताओं तथा बीयर आयातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले Beer Institute ने लंबे समय से कर और व्यापार नीति को अपने केंद्रीय मुद्दों में रखा है। इस छोटी सूची में हेम्प का शामिल होना दिखाता है कि पेय उद्योग उन उभरती श्रेणियों पर कितना ध्यान दे रहा है, जो खुदरा बिक्री और उपभोक्ता खर्च के लिहाज से बीयर के करीब हैं।

एल्यूमिनियम अब भी बड़ी चिंता है, क्योंकि बीयर कारोबार में कैन पैकेजिंग की बुनियादी सामग्री हैं। एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ाने वाली कोई भी नीति आपूर्ति श्रृंखला में तेजी से असर डाल सकती है—कैन निर्माताओं से लेकर ब्रुअरी और फिर वितरकों तथा खुदरा विक्रेताओं तक। बीयर निर्माताओं, खासकर पैकेज्ड उत्पादों पर अधिक निर्भर कंपनियों के लिए, धातु की बढ़ी लागत मुनाफे का मार्जिन घटा सकती है या कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकती है। इसका दबाव बीयर से आगे भी जा सकता है, क्योंकि डिब्बाबंद कॉकटेल, हार्ड सेल्टज़र, शीतल पेय और एनर्जी ड्रिंक भी इसी पैकेजिंग व्यवस्था पर निर्भर हैं।

कर नीति एक और ऐसा मुद्दा है जिसके व्यापक नतीजे हो सकते हैं। संघीय उत्पाद शुल्क और बीयर से जुड़े अन्य कर उत्पादन लागत, कीमतों और निवेश के फैसलों को प्रभावित करते हैं। उद्योग संगठनों का वर्षों से तर्क रहा है कि अधिक अनुकूल कर व्यवस्था से भर्ती, पूंजीगत खर्च और नए उत्पादों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि करों का अधिक बोझ उन उत्पादकों की गुंजाइश सीमित कर सकता है जो पहले ही सामग्री, माल ढुलाई और श्रम की बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं। क्रॉफर्ड के जोर से संकेत मिलता है कि Beer Institute को नए संसदीय समीकरण के तहत कर संबंधी बहसें जारी रहने की उम्मीद है।

पेय कंपनियों की नजर हेम्प से बने उत्पादों के तेजी से बदलते बाजार पर है और इसके साथ ही हेम्प नीति चर्चा में अधिक प्रमुख हो गई है। यह मुद्दा संवेदनशील है, क्योंकि कानूनी और नियामकीय ढांचा अभी विकसित हो रहा है। अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग रुख अपनाए हैं और संघीय एजेंसियों तथा सांसदों ने अभी यह तय नहीं किया है कि इन उत्पादों का वर्गीकरण, विपणन या बिक्री कैसे होनी चाहिए। बीयर उत्पादकों और अन्य पेय कंपनियों के लिए यह अनिश्चितता मायने रखती है। इससे उपभोक्ता खर्च के लिए प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है, यह तय हो सकता है कि कौन-सी कंपनियां कौन-से उत्पाद बेच सकती हैं और उन कंपनियों पर अनुपालन का कितना बोझ पड़ेगा जो इससे जुड़ी अन्य श्रेणियों में उतरना चाहती हैं।

Beer Business Daily की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि Beer Institute इन तीनों मुद्दों को दीर्घकालीन चिंताओं के बजाय तत्काल प्राथमिकताएं मानता है। यह दिखाता है कि वॉशिंगटन में नीतिगत फैसले बीयर की दुकान की शेल्फ तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। एल्यूमिनियम नीति कैन की लागत को प्रभावित कर सकती है। कर संबंधी फैसले ब्रूइंग और वितरण की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं। हेम्प के नियम इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि दुकानों में बीयर के बगल में कौन-से उत्पाद रखे जाते हैं और पेय कंपनियां भविष्य की मांग के लिए कैसी योजना बनाती हैं।

कांग्रेस पर यह ध्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कई सवालों पर कानून बनाने की जरूरत होती है या संघीय एजेंसियों की सीधी भूमिका के बावजूद सांसदों का उन पर खासा प्रभाव रहता है। व्यापार उपाय, टैरिफ नीति और कर कानून वॉशिंगटन की राजनीति के जरिए तय होते हैं। हेम्प पर निगरानी का स्वरूप नियामकों से प्रभावित होता है, लेकिन यह कांग्रेस की कार्रवाई और दबाव से भी जुड़ा है। दलगत नियंत्रण में बदलाव से समितियों का नेतृत्व, सुनवाई की गति और कुछ प्रस्तावों के आगे बढ़ने की संभावना बदल सकती है।

बीयर उत्पादकों के लिए दांव केवल सबसे बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं हैं। छोटे क्राफ्ट उत्पादक अक्सर पैकेजिंग और माल ढुलाई की लागत में उतार-चढ़ाव से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी खरीद क्षमता कम होती है और अचानक बढ़ोतरी का बोझ उठाने की गुंजाइश भी सीमित रहती है। तेजी से बदलते नियामकीय बदलावों पर नजर रखने और उनका

जवाब देने के लिए उनके पास संसाधन भी कम हो सकते हैं। राजनीतिक बदलाव के दौर में व्यापार संगठनों की पैरवी को यह और महत्वपूर्ण बनाता है।

Beer Business Daily के ब्यौरे के मुताबिक, क्रॉफर्ड की टिप्पणियों से पता चलता है कि Beer Institute अपनी नीति-प्राथमिकताओं को स्पष्ट और सीमित रखकर इस बदलाव के लिए तैयारी कर रहा है। संगठन यह संकेत देता दिखता है कि चुनावी नतीजों से वॉशिंगटन का माहौल बदल सकता है, लेकिन उद्योग की बुनियादी चिंताएं वही हैं: कच्चे माल और अन्य इनपुट की लागत, कर व्यवस्था और उभरते उत्पादों से जुड़े नियम।

यह एजेंडा पूरे पेय क्षेत्र के लिए अहम है, क्योंकि बीयर का कारोबार अलग-थलग नहीं चलता। बीयर निर्माता शेल्फ की जगह, पैकेजिंग सामग्री और उपभोक्ता खर्च के लिए वाइन, स्पिरिट, रेडी-टू-ड्रिंक कॉकटेल और गैर-अल्कोहल पेयों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। एल्यूमिनियम की लागत में बदलाव एक साथ कई श्रेणियों में असर डाल सकता है। करों में बदलाव से अल्कोहल पेय की विभिन्न श्रेणियों के बीच कीमतों का संतुलन बदल सकता है। हेम्प के नए नियम कुछ कंपनियों के लिए अवसर खोल सकते हैं और दूसरी कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी दबाव बढ़ा सकते हैं।

Beer Business Daily ने क्रॉफर्ड की टिप्पणियों को Beer Institute की रणनीति में बड़े बदलाव के रूप में पेश नहीं किया। इसके बजाय, वे ऐसे समय में समूह की मुख्य संघीय प्राथमिकताओं में निरंतरता का संकेत देती हैं, जब कई कंपनियां फिर से आकलन कर रही हैं कि राजनीति और नियमन मांग तथा लागत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इस लिहाज से, एल्यूमिनियम, करों और हेम्प पर संगठन का ध्यान अमेरिकी पेय कारोबार में फैसलों को आकार दे रहे दबावों की संक्षिप्त तस्वीर पेश करता है।